www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 105 | जौनपुर शनिवार, 29 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग पहुंचा टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में चुनाव आयोग का रुख किया। टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। टीम की अगुवाई राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ' ब्रायन ने की। उनके साथ लोकसभा में डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, डोला सेन, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक बराइक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक लिखित शिकायत सौंपी। उनका आरोप है कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लाखों मतदाताओं के नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। खास तौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों और तृणमूल समर्थक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग की देखरेख में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करके उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। संविधान के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारत के ही नागरिक को मतदान का अधिकार है। केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में बड़ी संख्या में कई अन्य देशों के भी नागरिक रह रहे है।

कांग्रेस अपनी विफलता छिपाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही – खंडेलवाल

राजगढ़, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर हमला बोला है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में एसआईआर को लेकर आयोजित कार्यशाला में खंडेलवाल ने कहा, श्श्कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था। कांग्रेस आजादी के आंदोलन के समय एक अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक मंच था, जिसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल होकर देश को आजाद कराने का कार्य कर रहे थे। देश के आजाद होने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए इसका उपयोग किया। नेहरू परिवार आज भी इसका उपयोग सत्ता के लिए कर रहा है, जबकि कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठन के समय से लेकर आज तक एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा ने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। कार्यकर्ता आधारित भाजपा संगठन आज भी अपनी विचारधारा पर अडिग है। एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची के शुद्धिकरण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्यक है।

गीता ने सिखाया- अत्याचारियों का अंत भी जरूरी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

उडुपी, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एकदिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंच गए हैं। जहां उडुपी में जगद्गुरु श्री श्री सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामीजी ने विश्व गीता पर्याय– लक्ष्य कंठ गीता परायण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्उडुपी आना मेरे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि उडुपी जनसंघ और भाजपा के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में, उडुपी के लोगों ने हमारे जनसंघ के वी.एस. आचार्य को यहां के नगरपालिका परिषद में जिताया था... आज हम देश भर में जो स्वच्छता अभियान देख रहे हैं, उसे उडुपी ने पांच दशक पहले अपनाया था.. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, श्हमारे समाज में मंत्रों, गीता के श्लोकों का पाठ शताब्दियों से हो रहा है पर जब एक लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं.. . तो ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन, मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, नई शक्ति देती है... यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति भी है, यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है इसलिए आज लक्ष कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, श्यहां आने से तीन दिन पहले मैं अयोध्या में था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है... राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है सारा देश इसे जानता है।श उन्होंने कहा, श्आज हमारी श्सबका साथ, सबका विकासश, श्सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायश की नीतियां भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों से प्रेरित हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की मदद करने का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का आधार बनती है... भगवान श्री कृष्ण हमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं ।

ब्रह्मोस मिसाइल डील फाइनल चरण में, राजनाथ ने इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री को दी प्रतिकृति

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के सौदे पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बृहस्पतिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष श्याफ्री स्यामसुद्दीन के बीच द्विपक्षीय रक्षा वार्ता हुई। इस बैठक के दौरान राजनाथ ने स्यामसुद्दीन को ब्रह्मोस मिसाइल की एक प्रतिकृति भेंट की। राजनाथ ने इसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। यह एक ठोस सामरिक संकेत है कि जल्द ही इस सौदे पर मुहर लग सकती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर कई उच्च स्तरीय वार्ताएं हो चुकी हैं। इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और पीएम मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता में ब्रह्मोस का सौदा शीर्ष पर था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई–30 विमान से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में बेहद सटीकता से लक्ष्य पर वार किया था। जिसके बाद इस पर इंडोनेशिया का भरोसा और बढ़ा है। द्विपक्षीय रक्षा वार्ता के दौरान राजनाथ ने कहा कि दशकों से दोनों देशों के रक्षा संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की नींव पर बने हुए हैं। आज का दिन हमारे रक्षा सहयोग की बढ़ती ताकत का सबूत है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते हैं। बहुलवाद, समावेशिता और कानून के शासन के मूल्य दोनों देशों में पाए जाते हैं।

शिंदे सेना पर वंशवाद का आरोप, सहयोगी भाजपा नाराज

मुबई, (एजेंसी)। शिवसेना (शिंदे गुट) ने बदलापुर नगर परिषद चुनाव में प्रभावशाली म्हात्रे परिवार के छह सदस्यों को टिकट देकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। स्थानीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति, नगर प्रमुख वामन म्हात्रे ने अपनी पत्नी, बेटे, भाई, भाभी और भतीजे के साथ खुद को मैदान में उतारा है। परिषद की 49 सीटों में से छह सीटें एक ही परिवार को आवंटित करने के फैसले की तीखी आलोचना हुई है, खासकर भाजपा की ओर से, जिसके साथ वह राज्य सरकार में सत्ता साझा करती है। भाजपा ने शिंदे सेना पर योग्य उम्मीदवारों की कमी और खुलेआम भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे ने वंशवाद बनाम पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान पर बहस छेड़ दी है। चुनावों में म्हात्रे परिवार की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। 2015 के नगर परिषद चुनावों में, परिवार के चार सदस्य पार्षद चुने गए थे। इस बार, उनके

छह उम्मीदवारों तक पहुँचना स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में सबसे चर्चित घटनाक्रमों में से एक बन गया है। विवाद को और बढ़ाते हुए, शिंदे सेना ने पूर्व पार्षद प्रवीण राउत के परिवार को भी तीन टिकट दिए हैं, जिनमें वे, उनकी पत्नी शीतल राउत और उनकी साली विजया राउत शामिल हैं। परिवार–आधारित टिकट वितरण के इस दूसरे दौर ने पार्टी के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है, जहाँ लंबे समय से पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बोलने से हिचकिचा रहे हैं। हालांकि, परिवार का प्रभाव केवल शिंदे गुट तक ही सीमित नहीं है। भाजपा में, शहर अध्यक्ष राजेंद्र घोरपड़े पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी रचिता घोरपड़े को पार्टी ने परिषद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना (यूबीटी) खेमे में, प्रशांत पलांडे और प्राची पलांडे भी एक ही वार्ड में दो अलग–अलग पैनलों से चुनाव लड़ रहे हैं।

कुंभ 2027 अखाड़ों में चल रही रार के बीच बैठक में शामिल हुए सीएम धामी

देहरादून, (एजेंसी)। अखाड़ों में चल रही रार के बीच होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। 2027 अर्द्धकुंभ मेले को लेकर भी चर्चा की गई। कुल 97 दिनों के भव्य कुंभ में चार प्रमुख शाही स्नान होंगे। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा और अप्रैल में कुंभ का समापन होगा। चर्चा के दौरान सभी बातों पर संतों ने सहमति जताकर अखाड़ों से उठी पूर्व की आपत्तियों पर विराम लग गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर सभी तेरह अखाड़ों के साधु संतों का सम्मान किया। इस दौरान कुंभ हरिद्वार कार्यक्रम के लिए विशेष

पंडाल बनाया गया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप समेत कई विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने अखाड़ों के प्रतिनिधियों व हितधारकों संग कुंभ की व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर रायशुमारी की। इसमें शाही स्नान से लेकर हर समस्याओं के समाधान तथा भव्य–दिव्य कुंभ की रूपरेखा तैयार की गई। सीएम की बैठक से पूर्व बृहस्पतिवार को अधिकारी बैरागी से लेकर निर्मोही, निरंजनी से जूना समेत सभी 13 अखाड़ों में पहुंचकर समन्वय बनाने में जुटे रहे। पहले बैरागी संतों ने अखिल भारतीय श्रीपंच निर्मोही अनी अखाड़े में मेलाधिकारी सोनिका सिंह का स्वागत किया। संतों से चर्चा के दौरान मेलाधितकारी ने कहा कि सरकार और संतों के समन्वय से कुंभ मेले को दिव्य और भव्य रूप से संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज सभी पूज्य संतों ने कुंभ मेले के लिए अपना पूरा आशीर्वाद और सहयोग देने का वादा किया, क्योंकि कुंभ मेला होता है, इसलिए हमारे पूज्य संत समाज का इसमें बड़ा रोल होता है। हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संत आज यहां मौजूद थे।

नक्सलवाद-आतंकवाद पर होगा वार, अमित शाह और पीएम मोदी होंगे शामिल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से शुरू हो रहे पुलिस महानिदेशकों–महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार देर रात यहां पहुंचे। यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी 29 और 30 नवंबर को सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तथा उनके शुक्रवार देर शाम तक यहां पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन के मद्देनजर नवा रायपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री शाह बृहस्पतिवार देर रात विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका स्वागत

किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सम्मेलन का उद्देश्य पुलिस के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा ''विकसित भारत'' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ''सुरक्षित भारत'' बनाने के लिए भविष्य का खाका तैयार करना है। बयान के अनुसार, ''विकासशील भारतरू सुरक्षा आयाम'' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद– निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस सेवा में फॉरेंसिक विज्ञान एवं कृत्रिम मेधा के उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। बयान में कहा गया कि यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट और सार्थक चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। बयान के अनुसार, यह पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालनात्मक, संरचनात्मक और कल्याणकारी चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ–साथ अपराध से निपटने, कानून–व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं को विकसित करने और साझा करने में भी मदद करता है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वार्षिक सम्मेलन में निरंतर रुचि दिखाई है, खुले संवाद को प्रोत्साहित किया है और ऐसा माहौल बनाया है जहां पुलिस व्यवस्था पर नए विचार उभर सकें। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह राज्य मंत्री, राज्यों–केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे।

नेपाल नोट मामले में केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए – पवन खेड़ा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को नेपाल द्वारा एनपीआर 100 के लिए नया नोट जारी करने के कदम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस नोट में लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के विवादित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मानचित्र दिखाया गया है। एएनआई से बात करते हुए, पवन खेड़ा ने कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। भारत सरकार को समझदारी और सख्ती से काम लेने की जरूरत है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? नेपाल ने गुरुवार को एनपीआर 100 के लिए अपना नया नोट जारी किया, जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मानचित्र दिखाया गया है। यह बैंक नोट आज प्रचलन में आ गया। एक सार्वजनिक सूचना में, नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी), जो कि नेपाल का केंद्रीय बैंक है, ने कहा कि नए जारी किए गए एनपीआर 100 मूल्यवर्ग के नोट को

श्प्रामाणिकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए परिष्कृत सुरक्षा और पहचान तत्वों को शामिल करते हुए डिजाइन किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में, एनआरबी ने एक चीनी कंपनी को नए बैंक नोटों की छपाई का काम सौंपा था। नेपाली मंत्रिमंडल ने मई 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में एनपीआर 100 मूल्यवर्ग के नोट के डिजाइन को मंजूरी दी थी। मुद्रण का ठेका चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था। 20 मई, 2020 को, नेपाल ने एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को शामिल करते

फिर सरकार बनने पर यूसीसी भी लागू करेंगे : हिमंत

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम विधानसभा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला अहम बिल पास कर राज्य में एक बड़ा कानूनी बदलाव कर दिया। इस बिल के पारित होने के साथ ही बहुविवाह को आपराधिक कृत्य माना जाएगा और दोषी को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और आश्वासन दिया कि अगर वह अगले कार्यकाल में फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया जाएगा। गुरुवार को पारित इस बिल में साफ किया गया है कि यह कानून सभी समुदायों पर लागू होगा। हालांकि, अनुसूचित

जनजाति (एसटी) के लोगों और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने साफ कहा कि बिल किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य सभी समाजों में समानता और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बहस के दौरान सरमा ने कहा कि बहुविवाह सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं है, हिंदू समाज में भी ऐसे मामले मिलते हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि इसे इस्लाम–विरोधी बिल बताने वाली धारणाएं गलत हैं। सीएम ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे संशोधन प्रस्ताव वापस लें ताकि पूरा सदन एकमत होकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत संदेश दे सके। सरकार की अपील के बावजूद एआईयूडीएफ और सीपीआई(एम) ने अपने संशोधन प्रस्ताव वापस नहीं लिए। वोटिंग के दौरान उनके प्रस्तावों को आवाज मत से खारिज कर दिया गया। सरकार ने इसे महिलाओं के हित में लाया गया सामाजिक सुधार बताया, जबकि विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए सरमा ने सदन में घोषणा की कि अगर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद वह फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो नए कार्यकाल के पहले सत्र में ही यूसीसी बिल पेश किया जाएगा।

राहुल गांधी ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली–एनसीआर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर पोस्ट कर कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिलाकृवे अपने ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली हवा से छोटे–छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी केंद्र सरकार हाथ पर

हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए, ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। राहुल गांधी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे यही कहती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। वे डरे हुए और गुस्से में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे सामने भारत के बच्चों के दम घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार जल्द ही कोई प्लान क्यों नहीं तैयार करती? उन्होंने कहा कि भारत को एयर पॉल्यूशन पर तुरंत संसद में बहस और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त लागू करने लायक एक्शन प्लान की जरूरत है। हमारे बच्चों को साफ हवा मिलनी चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे उन महिलाओं से बात करते नजर आ रहे हैं, जो दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जता रही हैं। वीडियो में महिलाएं अपने बच्चों पर प्रदूषित हवा से पड़ रहे असर के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि उनका स्वास्थ्य दिन–ब–दिन खराब होता जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को अभी नजरअंदाज किया गया तो इससे देश को लंबे समय तक स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही महिलाओं ने कहा कि सरकार सही हेल्थ एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर रही है ।

संपादकीय

भारत की कठिनाइयां बढ़ी

शेख हसीना के खिलाफ ट्रिब्यूनल के फैसले से बांग्लादेश में सियासी मेलमिलाप की संभावना और घट गई है। दूसरी तरफ इससे भारत की कठिनाइयां बढ़ी हैं। देश छोड़ने के बाद से हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री भारत में रह रहे हैं। जब किसी देश में सत्ता तंत्र में आमूल बदलाव आ जाता है, तो पूर्व शासन से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई या उन पर चले मुकदमों की निष्पक्षता हमेशा संदिग्ध रहती है। ऐसे मामलों में अक्सर बदले की भावना से कार्रवाई होती है, जिसमें अभियुक्तों को अपना बचाव करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। बांग्लादेश में जो हुआ, वह भी इस सामान्य चलन से अलग नहीं है। बांग्लादेश के कथित इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है और उन्हें सजा–ए–मौत सुना दी है। यही दंड हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे असदुजम्मां खान कमाल को भी सुनाया गया है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को उन कथित अपराधों के लिए दोषी पाया, जो पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए थे। इन प्रदर्शनों में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई। ट्रिब्यूनल के ताजा फैसले से बांग्लादेश में सियासी मेलमिलाप की संभावना और घट गई है। दूसरी तरफ इससे भारत की कठिनाइयां बढ़ी हैं। अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद से हसीना और कमाल दोनों भारत में रह रहे हैं। अब चूंकि वे दोनों सजायाफ्ता मुजरिम हैं, इसलिए उन्हें पनाह दिए रहना भारत के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। बांग्लादेश ने इसके तहत शेख हसीना और कमाल को वापस भेजने की मांग रख दी है। इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में बांग्लादेश संधियों एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति भारत की वचनबद्धता पर सवाल खड़े करेगा। लेकिन दोनों को सजा–ए–मौत देने के लिए बांग्लादेश भेजने से अपने लिए अनुकूल रहे नेताओं को संरक्षण देने में भारत की विफलता का संदेश जाएगा। स्पष्टतरू यह एक मुश्किल चुनौती है, जिसमें वर्तमान सरकार के कूटनीति कौशल का इम्तहान होगा। पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश के रुख से भारत के लिए अन्य मुश्किलें भी बढ़ी हैं। खासकर पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ी निकटता से भारत के सामने सुरक्षा एवं विदेश नीति संबंधी नई चुनौतियां दरपेश आई हैं। अब प्रत्यर्पण संधि के पालन का सवाल इसमें एक नया पेंच बन कर जुड़ गया है।

सिद्धारमैया, न शिवकुमार कर्नाटक की लड़ाई में मल्लिकार्जुन खरगे ने सेट कर ली अपनो गोटी

अभिनय

हिंदी में कहे तो शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि दिया हुआ वचन निभाया जाए। चाहे जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी व्यक्ति। खुद मैं भी उसमें शामिल हूं। हर किसी को अपनी कही हुई बात पर चलना पड़ता है। 27 नवंबर 2025 को 8रू21 मिनट पर 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चाणक्य और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक पोस्ट किया। राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर सत्ता हस्तांतरण समझौते, यानी दो ढाई साल बाद मुख्यमंत्री पद सौंपे जाने, का संकेत माना गया। शिवकुमार की पोस्ट के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब देते हुए लिखा ।ॅवतक पे दवज चवूमत नदसमे पज इमजजमते जीमॅवतसक वित जीम चमवचसम. इसे राजनीतिक विश्लेषक उनके पूरे कार्यकाल तक सीएम बने रहने के दावे के रूप में देख रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम पद के लिए डीके शिवकुमार सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट थे। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट भी उन्हीं को गया था। मगर सीएम सिद्धारमैया को बनाया गया तब से ही हर रोज कयास लगाए जा रहे थे कि बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद डीके शिवकुमार ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि सार्वजनिक रूप से खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इसके लिए अपना प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। लेकिन डीके शिवकुमार मानने के लिए तैयार नहीं है। डीके शिवकुमार का कहना है कि जिस वक्त 2023 में नतीजे आए थे उस वक्त यह पार्टी आलाकमान ने तय किया था गुप्त कमरे में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि ढाई साल पहले ढाई साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और आखिर के जो ढाई साल हैं उसमें डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे 20 नवंबर को वो ढाई साल का वक्त पूरा हो चुका है। ऐसे में डी के शिवकुमार अब जो उनके साथ डील हुई थी उस डील पर आए हैं कि ये डील अब पूरी होनी चाहिए लेकिन सिद्धार्थ रमैया का कहना है कि आलाकमान अब तय करेगा। दरअसल, 10 मई 2023 को जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिली। 224 सीटों वाले राज्य में 223 सीटों पर लड़कर कांग्रेस को 135 सीटें आई। जुलाई 2019 में जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के 13 विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई थी और सेंटर के बैकअप के बाद लगातार मजबूत दिख रही थी कांग्रेस की यह जीत निश्चित रूप से एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद कांग्रेस का एक चेहरा स्टेट के बाहर भी काफी चर्चित हुआ। लोगों ने उसे कांग्रेस का चाणक्य माना और नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे फेवरेट चेहरा नाम था डी के शिव कुमार। डीके शिवकुमार ही कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे और पार्टी के लिए योजना बनाने से लेकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में वही हमेशा फ्रंट पर दिखे। इसलिए जीत का बड़ा क्रेडिट या कहें तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को गया। मगर कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भरोसा जताया। एक बड़ा कारण यह भी कि सिद्धार्थ रमैया का कद बहुत बड़ा है और पुराने नेता उनके फेवर में ज्यादा थे। यह बिल्कुल वही कहानी है जैसा हम राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखते हैं। जो मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच देखा। कुमार को बस इस चीज का एज है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल उनके पास है। लेकिन यह सब बस संभावनाएं हैं। डीके शिवकुमार सार्वजनिक रूप से यही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हितों के आगे पार्टी का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर फिलहाल सबकी नजर इसी पर है और ताजा हालात को देखते हुए यह तो जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के पास एक बड़ा पॉलिटिकल टेंशन सामने है। जिसका नतीजा कर्नाटक के भीतर ऑपरेशन लोटस 2.0 के लिए भी रास्ता खोल सकता है। 89 के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है 135 विधायकों के

साथ। बीजेपी के पास 66 हैं और जेडीयू के पास 19 हैं। सिर्फ बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस 28 विधायकों की जरूरत है। सिद्धारमैया बाकी विकल्पों पर भी बात कर सकते हैं। वैसे विकल्प जिसमें पावर टशल पर विराम लगाने के लिए अपने किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री बनवाना या फिर इस शर्त पर आना कि डीके शिवकुमार को छोड़कर दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें समस्या नहीं होगी। ऐसे में डीके शिव कुमार भी अपनी तरफ से किसी को पुश कर सकते हैं। ऐसे में एक नाम जिस पर पार्टी विचार कर सकती है गृह मंत्री जी परमेश्वर का आता है। वह भी एक मजबूत और प्रभावी नेता हैं। उन्होंने पहले भी खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा है कि वह हमेशा से मुख्यमंत्री के रेस में रहे हैं। वैसे दो और प्लेयर हैं वहां पर। वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक मलिकार्जुन खड़गे है जो कि खुद आलाकमान है। उनकी कर्नाटक सीएम बनने की बड़ी इच्छा है। कर्नाटक को जिंदगी में पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री जरूर मिलना चाहिए। दलितों की आबादी भी 11: है। अगर उनकी उम्र आड़े आती है तो इन सब से अलग प्रियांक खड़गे अलग गोटी सेट करने में लगे हैं।

अरुणाचल पर चीन का दावा भाजपा की गलती का नतीजा

मयंक

चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति और हड़पने वाली नीयत का परिचय देते हुए फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति और हड़पने वाली नीयत का परिचय देते हुए फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान (अरुणाचल प्रदेश का चीन में दिया नाम) हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। गौरतलब है कि चीन का यह बयान उस वक्त आया है, जब लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम वांगजॉम थांगडॉक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी की गई। पेम ने आरोप लगाया था कि 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। इस दौरान चीनी अधिकारियों ने उन्हें रोका और उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया था, क्योंकि उसमें जन्मस्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। पेम ने यह भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद कई आव्रजन अधिकारी और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का तंज कसा। पेम ने कहा कि जो 3 घंटे का ट्रांजिट होना चाहिए था, वह उनके लिए 18 घंटे का परेशान करने वाला हादसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें न सही जानकारी दी गई, न ठीक से खाना मिला और न ही एयरपोर्ट की सुविधाएं इस्तेमाल करने दी गईं। किसी तरह उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया, तब जाकर उन्हें मदद मिली। दूसरे मुल्क में भारतीय के साथ बदसलूकी का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल ही जब कागजात पूरे न होने पर अमेरिका में रह रहे सैकड़ों भारतीयों को जंजीरों से जकड़कर अमेरिकी सैन्य विमान से वापस भेजा गया, तब भी सवाल उठे थे कि मोदी सरकार इस अपमान पर चुप क्यों है। अपने नागरिकों के सम्मान और भारतीयता की गरिमा के लिए वह आगे क्यों नहीं आती। लेकिन मोदी सरकार ने तब तो अमेरिका का ही बचाव किया कि वे अवैध रूप से रहने वाले लोगों को निकाल रहे हैं और अब भी केवल मुंहजबानी बयान से ही काम चला रही है। चीन पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगा रही है, लेकिन इससे हालात बदलने वाले नहीं हैं। पेम वांगजॉम थांगडॉक के आरोपों पर चीनी प्रवक्ता माओ ने कहा कि, उनके साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या परेशान करने जैसा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि, एयरलाइन ने महिला को आराम, पानी और खाने की सुविधा भी दी। लेकिन इस प्रकरण के बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताना और भारत के अवैध कब्जे की बात करना यह जाहिर कर रहा है कि चीन की नीयत में कोई सुधार नहीं आया है। चीन के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। मगर इस तरह के बयान देने से अगर हालात सुधरते तो बात ही क्या थी। दरअसल मोदी सरकार पूरा सच सामने नहीं रख रही है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे आज की बात नहीं है। चीन तो यही दावा करता है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन को ऐसा दावा करने का हक बाजपेयी सरकार ने ही दिया था। चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन जब 1996 में भारत की

यात्रा पर आए थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी बातचीत ने चीन और भारत के रिश्ते को थोड़ी प्रगाढ़ता दी। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। हालांकि, बदले में चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा माना और सिक्किम के रास्ते भारत–चीन के बीच व्यापार की हामी भरी गई। लेकिन तिब्बत पर भारत की नीति में बदलाव कर अटल बिहारी वाजपेयी ने भूल की थी, क्योंकि इसके बाद चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे और बढ़ गए। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत कहता है। आजादी के बाद पं. नेहरू ने भी तिब्बत को चीनी शासन अधीन स्वीकार किया था, क्योंकि वह दौर हिंदी–चीनी भाई–भाई का था। लेकिन 1962 में चीनी हमले के साथ ही समझौता खत्म हो गया था, क्योंकि चीन की चालाकी नेहरूजी ने समझ ली थी। बाजपेयीजी ने इसमें भूल क्यों की और अब मोदी सरकार उस भूल को सुधार क्यों नहीं रही, ये सोचने वाली बात है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताने के लिए चीन वहां के पहाड़ों, नदियों और अन्य इलाकों के नाम मंदारिन में रखता है। 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर झांग योंगपान ने ग्लोबल टाइम्स को कहा था, शजिन जगहों के नाम बदले गए हैं वो कई सौ सालों से हैं। चीन का इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज है। पुराने समय में जांगनान (चीन में अरुणाचल को दिया नाम) के इलाकों के नाम केंद्रीय या स्थानीय सरकारें ही रखती थीं। झांग के मुताबिक जैंगनेम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया तो वहां की सरकार ने गैर कानूनी तरीकों से जगहों के नाम भी बदले। झांग ने ये भी कहा था कि अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलने का हक केवल चीन को होना चाहिए। नाम बदलने का सिलसिला अब तक कायम है। चीन ने इसी साल मई में अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले हैं। बीते 8 सालों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। तब भी विदेश मंत्रालय ने कहा था– इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने नाम बदलने में रचनात्मकता दिखाई है, लेकिन अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है। इस कोरी बयानबाजी से अब मोदी सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल की सुरक्षा रणनीतिक तौर पर काफी अहम है, क्योंकि तिब्बत, भूटान और म्यांमार तीनों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। यहां कमजोर पड़ना पूरे देश को खतरे में डालना होगा।

नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्व

अजीत द्विवेदी

क्रिकेट के खेल की तरह राजनीति को भी अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको भी इतनी प्रेडिक्टेबल बना दिया है कि जिसको राजनीति की ज्यादा समझ नहीं होती है वह भी कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसके बाद मजाकिया अंदाज में यह भी कहा जाता है कि चाहे जिसके साथ बनाएं लेकिन सरकार नीतीश ही बनाएंगे। हालांकि अब आगे शायद ऐसा नहीं हो पाए क्योंकि विधानसभा में संख्या का हिसाब इस बार कुछ अलग है। बहरहाल, चुनाव नतीजों में एनडीए के जीते विधायकों की बड़ी संख्या को छोड़ दें तो कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। चुनाव नतीजे और सरकार का गठन वैसे ही हुआ है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चूंकि यह लगातार पांचवीं बार नीतीश कुमार की निरंतरता के लिए दिया गया जनादेश है इसलिए नई सरकार को कोई हनीमून पीरियड भी नहीं दिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि पहले दिन से सरकार को अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करना होगा और पहले दिन से हिसाब मांगा जाएगा। ध्यान रहे सरकार के सामने कम से कम अभी राजनीतिक चुनौती नहीं है। हालांकि आगे इसके आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस समय अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास होगा उस समय चुनौती आएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक ऐसा नहीं होगा। सरकार के सामने कोई प्रशासनिक चुनौती भी नहीं है क्योंकि नौकरशाही वही है, जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के साथ काम कर रही है। उनकी पसंद के अधिकारी सभी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं और उनको पता है कि सरकार को किस एजेंडे को प्राथमिकता में रख कर काम करना है। इस बार चुनाव में भाजपा और जनता दल यू के बीच पहले से बेहतर तालमेल दिखा है। अब यह देखना होगा कि शासन चलाने में दोनों का तालमेल वैसा ही रहता है या नहीं? माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पहले से ज्यादा नियंत्रण रखने का प्रयास करेगी। इसके तीन कारण हैं। एक कारण तो यह है कि नीतीश कुमार की सेहत पहले जैसी नहीं है और वे खुद रोजमर्रा के कामकाज को संभालने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं। वह बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ऐसा पहली बार हुआ है। तीसरा कारण यह है कि बिहार में विकास की और लोक कल्याण की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा आवंटन मिलने की संभावना है, जिसके लिए बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। फिर सवाल है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्व की है। चुनाव से पहले सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए बड़े राजस्व की जरुरत है। यहां यह ध्यान रखने की जरुरत है कि पहले नीतीश का विपक्ष लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव होते थे, जो सरकार के ऊपर ज्यादा हमले नहीं करते थे क्योंकि उनको उम्मीद लगी रहती थी कि कब नीतीश के साथ सरकार बनाने का मौका मिल जाए! दूसरे वे हमला करते थे तो लोग उनसे उनके राज के बारे में पूछने लगते थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर के रूप में बिहार में एक सजग विपक्ष मौजूद है, जिसके ऊपर पहले के शासन का कोई बैगेज नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि सरकार की योजनाओं और वादों को पूरा करने पर उनकी नजर रहेगी। वे इसमें सरकार की विफलता का मुद्दा उठाएंगे। सरकार की शपथ के दिन महात्मा गांधी के भितिहरवा आश्रम में एक दिन का उपवास करके उन्होंने अपने इरादे बता दिए हैं। सो, सरकार को गंभीर हो जाना होगा। अभी एक करोड़ 51 लाख महिलाओं के खाते में 10–10 हजार रुपए गए हैं। बचे हुई करीब सवा करोड़ महिलाओं के खाते में यह रकम जानी है। उसके बाद लाखों महिलाओं को दो दो लाख रुपए देने का भी वादा है। इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? ऐसे ही एक करोड़ नौकरियों और रोजगार का वादा है, जिसके लिए लाखों सरकारी पद सृजित करने होंगे। सरकार ने उद्योग में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाने के वादे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली के बाद हर घर पर सोलर पैनल लगवाने का वादा है। सवाल है कि सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का क्या तरीका है? क्या केंद्र के अनुदान और देसी, विदेशी संस्थाओं के कर्ज के भरोसे इतने वादे किए गए हैं? ध्यान रहे बिहार पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है और हर दिन बिहार 63 करोड़ रुपया कर्ज के ब्याज के तौर पर चुका रहा है। सो, नया कर्ज बहुत सोच समझ कर लेना होगा। एक सवाल यह भी है कि शराबबंदी का क्या होगा? इससे सालाना 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खत्म करने का वादा किया था। यह नीतीश कुमार की लीगेसी है,।

अर्थव्यवस्था में डिजिटल छलांग के भरोसे उद्यमों का विकास संभव नहीं

आर. सूर्यमूर्ति

एनएसओ को अपने सैंपलिंग फ्रेमवर्क को फिर से डिजाइन करना, तिमाही अनुमानों की ओर बढ़ना, और हाई–फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पर जोर देना, सभी स्वागतयोग्य हैं। लेकिन आंकड़ों से आखिर में यह पता चलता है कि यह सेक्टर बहुत ज़्यादा फैला हुआ

है, तेजी से बदल रहा है, अपने आप डिजिटाइज हो रहा हैकृ फिर भी यह ऐसे माहौल का इंतजार कर रहा है जो इसे सिफ 'एक सेफ्ष्टीनेट से ज़्यादा बनने दे। भारत के अनौपचारिक क्षेत्र (अनइनकॉरपोरेटेड नॉन–एग्रीकल्चरल सेक्टर) के गत तिमाही के बुलेटिन, पहली नजर में, वैश्विक झटकों से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए एक मामूली जीत की तरह लगते हैंरू डिजिटल संरचना अपनाने की रफ्ष्तार तेजी से बढ़ रही है, उद्यम थोड़े आगे बढ़े हैं, और रोजगार स्थिर बना हुआ है। लगभग 39प्रतिशत उद्यम अब किसी न किसी रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसे सेक्टर के लिए एक चौंकाने वाला बदलाव है जो लंबे समय से खाता–बही और नकद लेन–देन पर टिका हुआ है। उद्यमों की संख्या बढ़कर 7.97 करोड़ हो गयी, रोजगार12.86 करोड़ पर बना रहा, और शहरी श्रमिकों को काम पर लेने में मजबूती आयी। लेकिन यह विस्तार की नहीं, बल्कि दबाव में ढलने की कहानी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो जरूरत की वजह से डिजिटाइज हो रही है, न कि बड़े सपने की वजह से, और एक अनौपचारिक क्षेत्र जो उस बोझ को बनाए रखने के लिए जरूरी उत्पादकता, तेजी या ढांचागत समर्थन हासिल किए बिना भारत के श्रम बाजार का बोझ उठा रहा है। एक सेक्टर जो उद्यम नहीं जोड़ रहा है, बल्कि तेजी से ऑनलाइन हो रहा है, वह बाहरी दबावों का जवाब दे रहा हैरू कस्टमर डिजिटल पेमेंट की मांग कर रहे हैं, बाजार ऑनलाइन हो रहे हैं, जीएसटी से जुड़े कम्प्लायंस में सख्ती हो रही है, और आपूर्ति श्रृंखला का तेजी से पता लगाने की क्षमता और ऑनलाइन इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ रही है। यह कोई डिजिटल क्रांति नहीं हैय यह जिंदा रहने का काम है।

द्यमों में मामूली बढ़ोतरीकृ लगभग 8 करोड़ में लगभग 3 लाखकृ नई उद्यमिता ऊर्जा का संकेत देने के लिए बहुत कम है। जब भारत 2000 के दशक में सबसे तेजी से बढ़ रहा था, तो उद्यम वृद्धि एक मुख्य वजह थीरू छोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बढ़े, रिटेल इकाइयां बढ़ीं, और ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर सर्विस व्यापार तेजी से बढ़े। आज का उद्यम आंकड़ा एक ऐसे क्षेत्र की ओर इशारा करता है जो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि बना हुआ है। विस्तार के बजाय, डेटा जो दिखाता है वह निरंतरता हैगंभीर बात रोजगार का कम्पोजिशन है। काम पर रखे गए कामगार का हिस्सा 24.38 प्रतिशत से बढ़कर 25.91 प्रतिशत हो गया है। यह छोटे लेवल पर एक सकारात्मक संकेत है कृ इसका मतलब है कि उद्यमों में इतना हौसला है कि वे वेतन का खर्च उठा सकें। लेकिन समष्टिस्तर पर तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में अभी भी लगभग 60प्रतिशत कामगार तो मालिक हैं, जो याद दिलाता है कि भारत का रोजगार आधार अभी भी ज़्यादातर स्वरोजगार, कम उत्पादकता वाला और झटकों के प्रति कमजोर है। स्व–शोषण पर हावी श्रम बाजार उस तरह का वेतन आधारित विकास नहीं दे सकता, जिसकी कई अर्थशास्त्रियों का कहना है, भारत को अभी तुरंत जरूरत है। अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर श्रमिकों को इसलिए काम पर नहीं लगा पा रहा है वे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि घरों के पास रोजगार के बेहतर अवसर नहीं हैं। यह श्रोजगार में लोच का फंदाय हैरू जब औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर गिरती है, तो अनौपचारिक क्षेत्र अपने आप बढ़ जाता है यह उछाल एक जाने–पहचाने सीजनल पैटर्न में फिट बैठता हैरू मजदूर खरीफ के मौसम के बाद खेती से लौटते हैं और छोटी वर्कशॉप, फैब्रिकेशन यूनिट, रिपेयर शॉप और घर से चलने वाले मैन्युफैक्चरिंग में फिर से लग जाते हैं। यह लेबर रोटेशन है, लेबर अपग्रेडिंग नहीं। सालों से, नीति बनाने वालों ने इन तिमाही उतार–चढ़ाव को लगातार मैन्युफैक्चरिंग में सुधार के संकेत के तौर पर गलत समझा है। शहरी–ग्रामीण तुलना अधिक वीभत्स है। शहरी कामगारों की संख्या 6. 61 करोड़ से बढ़कर 6.91 करोड़ हो गई, जो एक ही तिमाही में एक बड़ी बढ़ोतरी है। ग्रामीण रोजगार में मुश्किल से ही कोई बदलाव आया। यह बड़े मैक्रो संकेतक के मुताबिक हैरू उपभोग अभी भी शहरी उच्च–मध्य वर्ग के परिवारों से चलता है, ग्रामीण मांग अभी भी कमजोर है, और जरूरी चीजों– खासकर खाने की चीजों– में महंगाई ने समय–समय पर ग्रामीण वास्तविक आय को कम किया है। इसलिए, अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर का शहरी झुकाव भारत की रिकवरी को आकार देने वाले गहरे अंतर को दिखाता है। महिलाओं के रोजगार की बढ़ी मजबूती कृ कार्यबल का लगभग 29प्रतिशतकृ कुछ ढांचागत रूप से अच्छे संकेतों में से एक है। अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी घर से काम, माइक्रो–सर्विसेज और डिजिटल–इनेबल्ड स्वरोजगार की ओर बदलाव का संकेत देती है परन्तु इसकी भी सीमाएं हैं। अनौपचारिक, कम पूंजी वाले उद्यमों में केंद्रित महिलाएं मैक्रोइकॉनॉमिक उत्पादकता पर कोई खास असर नहीं डाल सकतीं। विकास पथ, कर्ज तक पहुंच, या औपचारिक आपूर्ति श्रृंखला से लिंक के बिना, महिलाओं के श्रम का लाभ कम विकास दर लूप में फंसा रहता है। भारत के विकास की कहानी तेजी से एक उलझन पर निर्भर होती जा हैरू वह यह कि अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिकीकरण बढ़ने पर भी कामगारों को काम पर लेते रहना चाहिएय उद्यमों को आगे बढ़ाने का फायदा उठाए बिना डिजिटाइज करना होगाय उत्पादकता न बढ़ने पर भी रोजगार बढ़ना चाहिएय और यह भी कि अर्थव्यवस्था को तब भी बढ़ना चाहिए जब उसका सबसे बड़ा जॉब–क्रिएटिंग सेगमेंट कम मार्जिन और कम बफर पर काम कर रहा हो। एनएसओ को अपने सैंपलिंग फ्रेमवर्क को फिर से डिजाइन करना, तिमाही अनुमानों की ओर बढ़ना, और हाई–फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पर जोर देना, सभी स्वागतयोग्य हैं। लेकिन आंकड़ों से आखिर में यह पता चलता है कि यह सेक्टर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तेजी से बदल रहा है, अपने आप डिजिटाइज हो रहा है कृ फिर भी यह ऐसे माहौल का इंतजार कर रहा है जो इसे सिफ 'एक सेफ्ष्टीनेट से ज़्यादा बनने दे। यह एक कड़वी सच्चाई हैरू भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वह सब कुछ कर रही है जो वह कर सकती है, लेकिन यह अकेले देश के विकास को बोझ ज़्यादा समय तक नहीं उठा सकती।

सौर ऊर्जा से रोशन होगी झोपड़ी, किसान चलाएंगे ट्यूबवेल-थ्रेसर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश अब नवीकरणीय ऊर्जा की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजधानी में आयोजित मंडलीय विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल आधारित नवाचार मॉडल्स पेश कर सभी का ध्यान खींचा। विद्यार्थियों ने दिखाया कि सौर ऊर्जा से न केवल झोपड़ी में उजाला किया जा सकता है, बल्कि किसानों के ट्यूबवेल और थ्रेसर भी चलाए जा सकते हैं। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज परिसर में बृहस्पतिवार से शुरू हुई तीन दिवसीय प्रदर्शनी में लखनऊ बाल निकुंज की कक्षा 11 की छात्रा अंशिका यादव ने 'सोलर पावर डेवलपमेंट' नाम से आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किया। उनके मॉडल में यह दर्शाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की झोपड़ियों पर भी सोलर पैनल लगाकर रात में बेझिझक रोशनी की जा सकती है, भले ही बिजली का

कनेक्शन न हो। इसी तरह बख्शी का तालाब राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र अभय सिंह ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन की तकनीक बताई। उनके मॉडल में यह दर्शाया गया कि जलते कचरे से निकलने वाली ऊर्जा को सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली में परिवर्तित कर इतना पावर जेनरेट किया जा सकता है कि किसान अपने कृषि उपकरण आराम से चला सकें। इससे उन गांवों में भी ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है जहां बिजली की सुविधा सीमित है। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार के अनुसार तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी के परिणामों की घोषणा 29 नवंबर को की जाएगी। कुल 59 नवाचार मॉडल प्रदर्शनी में शामिल हुए, जिनमें करीब 30 मॉडल किसी न किसी रूप में सोलर ऊर्जा से जुड़े हैं। प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार ने बताया कि लखनऊ से 31, रायबरेली से 5, सीतापुर से 16, लखीमपुर खीरी से 6 और उन्नाव से 1 मॉडल बाल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं। शिक्षकों की ओर से लखनऊ से 7 और लखीमपुर से एक टीएलएम प्रदर्शित किया गया है।

लखनऊ में आपदा प्राधिकरण भवन निर्माण का निरीक्षण

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री हृषिकेश भास्कर याशोद ने गुरुवार को गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ के सेक्टर–7 में प्राधिकरण के लिए बन रहे निर्माणाधीन भवन का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता और समयसीमा को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।श्री याशोद ने संबंधित कार्यदायी संस्था के अभियंता और ठेकेदार को निर्देश दिया कि प्रत्येक दशा में भवन का कार्य मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण रूप से 31 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण कराया जाए। उन्होंने भवन के विभिन्न हिस्सों जैसे आपातकालीन संचालन केंद्र, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, मीटिंग हाल, लेक्चर हाल, क्लासरूम, डायनिंग एरिया, किचन और मेस का भी निरीक्षण किया।अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्राधिकरण में कार्यरत विशेष कार्याधिकारी श्री मान्धाता एवं लोक निर्माण विभाग की अभियंता श्रीमती अंशू मालिनी साहू को अपनी निगरानी में भवन का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सुरक्षा के दृष्टिगत उन्होंने रैम्प और सीढ़ियों पर तुरंत रेलिंग लगाने, भवन के सामने बने डिवाइडर को ठीक करने और भवन के अंदर वेंटिलेशन तथा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही भवन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की तत्काल तैनाती, प्रत्येक कमरे के सामने संख्या और संबंधित कर्मियों के नाम लिखवाने तथा प्रत्येक तल पर चाबी स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त खबरें

धनुष यज्ञ महोत्सव का आगाज

लखनऊ, (संवाददाता)। इंदिरानगर के अमराई गांव में बृहस्पतिवार को 110वें धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दोपहर दो बजे भूमि पूजन व हवन हुआ। तीन बजे से श्रीरामचरित मानस पाठ हुआ। 55 मातृशक्तियों ने 110 श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। शाम सात बजे

बच्चों ने प्रस्तुतियां दीं। लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने गायकी से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि उप्र मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी रहे। धनुष यज्ञ मंडल की ओर से आयोजित किया जा रहा महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। अध्यक्ष दिलीप कुमार मिश्र और उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे।

मंच पर राधाकृष्ण के प्रेम को किया जीवंत

लखनऊ, (संवाददाता)। योजना कॉलोनी श्रीरामलीला पार्क सेक्टर–ए सीतापुर मार्ग स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर का 34वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। बृहस्पतिवार को सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा शुरू हुई। कथावाचक आचार्य पं. गोविंद मिश्रा ने गीता का महत्व समझाया। वृंदावन के कलाकारों ने रासलीला की मनमोहक प्रस्तुतियां

पेश कीं। मंच पर राधाकृष्ण के प्रेम को जीवंत किया। पंडित गोविंद मिश्रा ने भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का महत्व समझाया। गीता में जीवन से जुड़ी हर परेशानी का हल है। गीता का पाठ करने से तनाव कम होता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। शाम छह बजे तक चली कथा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।

मेरठ मंडल में सड़क विकास को गति

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क निधि योजना के तहत मेरठ मंडल के विभिन्न जनपदों में स्वीकृत और चालू सड़क निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 11 लाख 46 हजार रुपये की अवशेष धनराशि जारी कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश भी दिए हैं।शासनादेश के अनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग हर स्थिति में 31 मार्च 2026 तक कर लिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2026 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर नियमित निरीक्षण और सत्यापन किया जाए।

सप्ताहभर का समय बचा, अब तक 45 फीसदी एसआईआर फर्म ही हुए जमा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में अब तक करीब 45 फीसदी मतदाताओं ने ही एसआईआर फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं। बाकी के फॉर्म जमा करवाने की जद्दोजहद जारी है। इसमें प्रशासनिक अफसरों के साथ मतदाताओं को भी सक्रियता दिखाने की जरूरत है। सभी का फॉर्म जमा हो सके, इसके लिए एडीएम व एसडीएम से लेकर सभी अफसर लगाए गए हैं। डीएम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म भरकर जमा कराने की आखिरी तारीख चार दिसंबर है। सहायक निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि राजधानी के सभी मतदाताओं तक एसआईआर फॉर्म पहुंच चुके हैं। बीएलओ एक–एक मतदाता का फॉर्म भरवाकर जमा करवाने में जुटे हैं। अब तक करीब 45 फीसदी फॉर्म ही जमा हुए हैं। चूंकि एक सप्ताह का ही समय बचा है, ऐसे में फॉर्म जमा करवाने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। मोहनलालगंज विधानसभा सीट में एसआईआर फॉर्म जमा करने वालों की संख्या ठीक है। मलिहाबाद, बीकेटी, सरोजनीनगर समेत कई सीटों पर कार्य धीमा है। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता फॉर्म जमा करने में ढिलाई बरत रहे हैं। अफसरों ने सख्ती शुरू की है। बीएलओ के साथ प्रधान, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी लगे हैं। चार दिसंबर के बाद फॉर्म नहीं जमा होंगे। नौ दिसंबर को सूची प्रकाशित होगी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में कुंडी खटकाओ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कार्यकर्ता घर–घर जाकर एसआईआर की जानकारी देकर फॉर्म भरवा रहे हैं। जिन्होंने भर लिया है, उनके फॉर्म जमा करवा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष बृहस्पतिवार को कैंट विधानसभा के बूथ संख्या 208 के मतदाताओं के घर गए और लोगों से संवाद कर जागरूक किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजन वर्मा, महामंत्री प्रशांत मिश्रा, चित्रा द्विवेदी, अनूप तिवारी, मनोज श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।

एमबीए के छात्रों को एयरटेल में रोजगार का मौका

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उसके संबद्ध महाविद्यालयों के एमबीए विद्यार्थियों के लिए एयरटेल कंपनी में नौकरी पाने का अवसर उपलब्ध हुआ है। विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल ने एयरटेल को अपने साथ जोड़ा है। कंपनी टेरिटरी सेल्स मैनेजर (एग्जीक्यूटिव ट्रेनी) पदों पर भर्ती करेगी। आवेदन के लिए अंतिम तिथि तीन दिसंबर निर्धारित की गई है। कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। कंपनी की ओर से विश्वविद्यालय को भेजी गई भर्ती सूचना के अनुसार चयनित विद्यार्थियों को शुरुआत में तीन माह की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान प्रदर्शन के आधार पर आगे फुल–टाइम पद के लिए चयन किया जाएगा। इंटर्नशिप अवधि में चयनित छात्रों को 25 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें बिक्री संचालन, बाजार विश्लेषण, चौनल पार्टनर प्रबंधन और फील्ड गतिविधियों का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले उम्मीदवारों को 4.5 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसमें फिक्स्ड और वैरिएबल वेतन के साथ मोबाइल, ब्रॉडबैंड व डीटीएच सेवाओं पर 4000 रुपये तक मासिक लाभ, यात्रा व भोजन भत्ता शामिल है। केंद्रीय प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. अनूप कुमार के अनुसार, इच्छुक विद्यार्थी आवेदन के लिए विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल से संपर्क कर सकते हैं। तीन दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद चयन करने के चरण, मूल्यांकन और साक्षात्कार की तिथियां जारी की जाएंगी।

संक्षिप्त खबरें

संयम बनने का संदेश देता है सुदामा चरित्र

लखनऊ, (संवाददाता)। नई जेल रोड स्थित धरमावत खेड़ा में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के आखिरी दिन बृहस्पतिवार को सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक दिनेशानंद मृदुल ने कहा कि सुदामा चरित्र व्यक्ति को संयम बनने का संदेश देता है। संयम होने से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। बच्चों का मनमोहक नृत्य व झांकी आकर्षण का केंद्र रही। रुक्मिणी और भगवान श्रीकृष्ण के वेश में बच्चों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फूलों की होली खेली गई। भक्तगण रंग–बिरंगी पुष्प वर्षा के बीच भक्ति और आनंद में झूम उठे और जयघोष से पंडाल गुंजायमान हो गया। आयोजक अमरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र जायसवाल, ऋत्विक प्रियदर्शी, वीरेंद्र विक्रम सिंह व आशुतोष मिश्रा, महेंद्र शुक्ला, राकेश कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनकर झूमे श्रद्धालु

लखनऊ, (संवाददाता)। बीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन श्रीकृष्ण–रुक्मिणी विवाह का वर्णन हुआ। कथावाचक किरीट भाई ने महारास,

कंस वध, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मिणी विवाह आदि प्रसंगों का वर्णन किया। कहा कि सच्ची भक्ति से मैं का भाव समाप्त हो जाता है। आस्था और विश्वास से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। मुख्य यजमान अतुल अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, महामंत्री रूपेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, अनुराग साहू, पंकज मिश्रा व भक्त मौजूद रहे।

धरने पर बैठे छात्र की 10 दिन बाद भी नहीं ली सुध

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) से निष्कासित पीएचडी शोधार्थी बसंत कुमार कनौजिया का धरना दसवें दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी शोधार्थी की सुध नहीं ली है। धरने पर बैठे बसंत के साथी छात्रों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक छात्र का नहीं है। पहले भी छात्रों के साथ अन्याय हो चुका है। मांग है कि बसंत की तत्काल वापसी की जाए। बसंत ने कहा कि न्याय मिलने तक धरना जारी रहेगा।

कानपुर की ओर से आने वाला ट्रैफिक शहीद पथ तिराहे से होगा डायवर्ट

लखनऊ, (संवाददाता)। कानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन व कार आदि शहीद पथ तिराहे से आगे कृष्णानगर–अवध चौराहे की तरफ नहीं जाएंगे। इन्हें शहीद पथ होकर ही शहर के भीतर आना होगा। बाइक, ऑटो, ई रिक्शा जैसे वाहनों पर रोक नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने इस व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति दौरे के कुछ ही दिन बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अवध चौराहे पर काफी समय से अंडरपास का काम चल रहा है। तीन दिन पहले निर्माण कार्य के दौरान पाइप लाइन फट जाने से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अवध चौराहे से आलमबाग जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वीआईपी रोड के जरिये ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। एडीसीपी ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अवध चौराहे व उसके आसपास यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। इस कारण अब इसमें बदलाव करने की तैयारी है। कानपुर की ओर से आने वाले प्रमुख ट्रैफिक को शहीद पथ के जरिये गुजारा जाएगा। शहीद पथ से यह शहर के भीतर अपने गंतव्य तक जा सकेगा। इससे अवध चौराहे पर यातायात का बोझ कम हो जाएगा। इस चौराहे पर केवल बाइक, ऑटो, ई–रिक्शा ही चलेंगे, जिससे यातायात संचालन आसानी से हो सकेगा। अभी कई वीआईपी कार्यक्रम हैं, इसलिए डायवर्जन कुछ दिन बाद ही लागू किया जाएगा। शहीद पथ तिराहे व उस मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती होगी। अवध चौराहे पर किए डायवर्जन से तमाम वाहन आलमबाग की ओर विपरीत दिशा में होकर चल रहे हैं। एडीसीपी ने बताया कि ऐसे वाहनों का ऑनलाइन चालान किया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को सीज भी किया जाएगा।

पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उच्चस्तरीय कार्यशाला में व्यापक मंथन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने, अधिक निवेश आकर्षित करने और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से आज योजना भवन में ''विकसित उत्तर प्रदेशद्2047'' विषय पर एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पर्यटन से जुड़े विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति–निर्माताओं, विशेषज्ञों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए।समूचे सत्रों में पर्यटन विकास की दीर्घकालिक रणनीतियों, नीति सुधारों, निवेश संभावनाओं और उभरते पर्यटन मॉडलों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात, पर्यटन महानिदेशक राजेश कुमार और पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, भावी संभावनाओं और विकास के लिए आवश्यक प्राथमिकताओं पर अपने सुझाव दिए। योजना विभाग, आयुष, संस्कृति विभाग, राज्य परिवर्तन आयोग तथा नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।अपने संबोधन में अवनीश अवस्थी ने कहा कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जिसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहती है। उन्होंने बताया कि घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर तथा विदेशी पर्यटक आगमन में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2025 में पर्यटकों की संख्या नए रिकॉर्ड की ओर अग्रसर है। उन्होंने 2019 के कुंभ और 2025 के महाकुंभ को पर्यटन विकास के मील के पत्थर बताते हुए कहा कि अयोध्या और काशी की तरह मथुरा में भी बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है।उन्होंने वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि सफाई, प्रशिक्षित युवाओं की सहभागिता, कॉरपोरेट साझेदारी, एक्सप्रेस–वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वे–साइड एमिनिटीज तथा सस्टेनेबल टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।कार्यक्रम में अमृत अभिजात ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देकर बताया कि पिछले आठ वर्षों में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी के बड़े विस्तार ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है। बेहतर कानून–व्यवस्था ने भी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैउन्होंने बताया कि प्रदेश में संग्रहालयों की समृद्ध श्रृंखला विकसित हो रही है और शौर्य संग्रहालय का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। सोशल मीडिया, स्मार्ट टूरिज्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, संस्कृति–आधारित पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटक सुरक्षा को नए दौर के पर्यटन के प्रमुख स्तंभ बताया गया।उन्होंने महाकुंभद्2025 में 45 दिनों के भीतर 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता और पर्यटन शक्ति का ऐतिहासिक उदाहरण बताया।लखनऊ को ''यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी'' की अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना, उन्होंने कहा, प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और पाक विरासत की अद्वितीय शक्ति को दर्शाता है।महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार ने स्थायी और समावेशी पर्यटन विकास मॉडल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों को आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाना पर्यटन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने वेलनेस टूरिज्म को उत्तर प्रदेश में केरल की तर्ज पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।कार्यक्रम में यूपीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि विभाग लंबी अवधि के प्रवास, सांस्कृतिक गतिविधियों और बेहतर अवसंरचना के उपयोग को ध्यान में रखते हुए।

कोशल साहित्य महोत्सव में सजी कला-संस्कृति की महफिल

लखनऊ, (संवाददाता)। तहजीब और रचनात्मकता की राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को कोशल साहित्य महोत्सव के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई। यूपी दर्शन पार्क में आयोजित इस चार दिवसीय उत्सव में साहित्य, कला, लोक–संस्कृति और संवाद का बेहतरीन संगम देखने को मिला। शहर के लेखक, कलाकार, शोधकर्ता और युवा साहित्य–प्रेमियों की मौजूदगी ने पहले दिन के माहौल को जीवंत बना दिया। उद्घाटन सत्र में शिक्षाविद डॉ. निशी पांडे, रंगकर्मी संदीप यादव, उद्यमी व फिल्म निर्माता अजय जैन और महोत्सव के संस्थापक प्रशांत कुमार सिंह ने बदलते समय में साहित्य की भूमिका, लोककलाओं के पुनरुत्थान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। कव्वाली और सूफी संगीत, सरहद से परे दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। कव्वाली में करुणा और आध्यात्मिकता शामिल है। रॉकस्टार जैसी कई फिल्मों की पहचान उनमें शामिल– श्कुन फाया कुनश्श जैसे सूफी संगीत और कव्वाली की वजह से है। ये बातें कोशल साहित्य महोत्सव के शुरुआती सत्र में प्रसिद्ध नृत्यांगना और सांस्कृतिक शोधकर्ता मंजरी चतुर्वेदी ने कहीं। मंच पर मौजूद कव्वाल गुफरान ने इस मौके पर– भर दे झोली, ख्वाजा मेरे ख्वाजा और अमीर खुसरो की– छाप तिलक सब छीनी जैसी कव्वाली सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। देवांशी सेठ से बातचीत में मंजरी चतुर्वेदी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि बॉलीवुड में कव्वाली अब कव्वाल से नहीं बल्कि किसी से भी गवा देते हैं जो गलत है। दूसरे सत्र– श्श्लाइट्स, कैमरा, लखनऊश्श के दौरान बातचीत में बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता व रंगकर्मी डॉ. अनिल रस्तोगी ने कहा कि कुछ वर्षों से लखनऊ में बहुत सी मशहूर फिल्मों की शूटिंग हुई और उन्हें काफी पसंद किया गया। कई कलाकार यहां से बड़ा नाम और काम कर रहे हैं। ओटीटी के लिए भी तमाम सीरीज यहां बन रही हैं। अब लखनऊ में भी बॉलीवुड जैसा सेटअप होना चाहिए। इस सत्र में सिनेमा, रंगमंच और मंचीय कलाओं पर लखनऊ की अमिट छाप पर गंभीर चर्चा हुई। संदीप यादव, अर्चना शुक्ला, अनिल रस्तोगी व देवाशीष मिश्रा ने कहा कि लखनऊ की नजाकत, ऐतिहासिकता और कहानी कहने की शैली भारतीय कलाओं को एक अलग आयाम दे रही है। तीसरे सत्र में श्श्द हिंदी हार्टलैंडश्श पर चर्चा हुई। लेखिका गजाला वहाब ने समाजसेवी जयंत कृष्णा व ज्योत्सना मोहन के सवालों के जवाब दिए। ज्योत्सना मोहन ने कहा कि कई बार लेखकों के लिए ऐसा होता है कि जहां लेखन की शुरुआत करते हैं और जहां समापन होता है, उसमें काफी दूरी हो जाती है। इस पर गजाला वहाब ने कहा कि वर्ष 2019 में दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट से शुरुआत की। हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो विरोधाभास है, उस पर भी काम किया। उसे करीब से समझा। सत्र में हिंदी हृदयभूमि के सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनसांख्यिक महत्व पर गहन चर्चा की, इसमें भारत की तकरीबन 40: आबादी प्रतिनिधित्व करती है। लोककथाओं का रोमांच अलग होता है। यह जीवन दर्शन प्रस्तुत करती हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं में धर्म–अध्यात्म व जीवन के गूढ़ रहस्यों का जो समन्वय मिलता है, वह जीवन का आधार बनता है। पौराणिक कथाओं, लोकथाओं व कहानी के विकास की ऐसी यात्रा पर कोशल महोत्सव के सत्र टेल्स वी कैरी में सुनने को मिला। सत्र में अमर चित्रकथा की संपादक रीना पुरी और लेखिका अश्विता जयकुमार ने अर्श अली के साथ पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं व कहानी की विकास यात्रा पर विचार–विमर्श किया। वक्ताओं ने कहा कि कहानियां स्मृति, पहचान व कल्पना की वाहक होती हैं।

वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर्स सेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर्स सेवा संस्थान, उ.प्र. ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संस्थान ने कहा कि प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पेन्शनर आज अनेक जटिलताओं से जूझ रहे हैं, जिनके समाधान के लिए शासन का ध्यान आवश्यक है। संस्थान के कोषाध्यक्ष रमाकान्त श्रीवास्तव द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि पेन्शनरों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने हेतु कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर तत्काल निर्णय लिया जाए जिनमें प्रमुख रूप से पेन्शनरों के लिए डिजिटल परिचय पत्र जारी करना,पेन्शनर सलाहकार समिति में संस्थान को सदस्य के रूप में शामिल करना, विधवा बहू को आश्रित की श्रेणी में मानकर पारिवारिक पेन्शन उपलब्ध ा कराना, पारिवारिक पेन्शन के लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण शामिल है। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों व शिक्षकों के चिकित्सा दावों के निस्तारण में हो रही देरी को दूर किया जाए। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से निजी चिकित्सालयों में उपचार के दौरान पेन्शनरों को हो रही असुविधाओं का भी समाधान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः अतिरिक्त पेन्शन वृद्धि लागू करने, राशिकरण की कटौती अवधि को 11 वर्ष तय करने तथा चित्रकूट कोषागार पेन्शन घोटाले की आड़ में पेन्शनरों की पेंशन को बैंक भेजने की कथित प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

संस्थान ने कोषागार सॉफ्टवेयर में संशोधन कर पेन्शनरों को जीवित प्रमाण पत्र एवं पेन्शन की अद्यतन जानकारी एमएमएस के माध्यम से उपलब्ध ा कराने की व्यवस्था करने पर भी बल दिया है। संस्थान ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे। इससे प्रदेश के लाखों पेन्शनरों को राहत मिलेगी और शासन की संवेदनशीलता का संदेश भी जाएगा

सामूहिक विवाह शर्म नहीं स्वाभिमान है सभी लोग करे सहयोग : चित्रगुप्त भगवान पूजन महासमिति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जेब्रा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह जो 7 दिसंबर को मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज मैदान जौनपुर में हो रहा है जो पुनीत कार्य हैं और सामूहिक विवाह शर्म नहीं स्वाभिमान है।

सामूहिक विवाह समारोह में श्री चित्रगुप्त भगवान पूजन महासमिति जौनपुर के संयोजक सरस चन्द श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता, अध्यक्ष मनोज अग्रहरी वरिष्ठ व्यापारी नेता,कायस्थ महासभा 7235 जौनपुर के जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट, राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद के जिलाध्यक्ष गिरिजेश श्रीवास्तव, चित्रांश महासभा के अध्यक्ष दयाल सरन श्रीवास्तव, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष डॉ उमाकांत श्रीवास्तव प्रिंसिपल, कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष अजय वर्मा अज्जू, श्री चित्रगुप्त सभी के अध्यक्ष रमेंद्र नाथ श्रीवास्तव, कायस्थ एकता मंच जिलाध्यक्ष दयाशंकर निगम सहित सभी संगठनों के पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे। उक्त आशय की जानकारी मीडिया प्रभारी विश्व प्रकाश श्रीवास्तव दीपक पत्रकार ने देते हुए सभी लोग से अनुरोध किया कि सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हो कर जेब्रा फाउंडेशन ट्रस्ट का सहयोग करे।

संक्षिप्त खबरें

यातायात माह पर बच्चों ने दिया ट्रैफिक ट्रैफिक जागरूकता का संदेश

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) श्री डालसिंह मेमोरियल स्कूल में यातायात माह पर निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता, बच्चों ने दिया ट्रैफिक

जागरूकता का संदेश दिया। यातायात माह नवंबर के तहत शनिवार को श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भदोही रेल मार्ग पर छह ट्रेनें रहीं लेट

भदोही, (संवाददाता)। ठंड अपना असर धीरे–धीरे ट्रेनों के परिचालन पर दिखने लगा है। भदोही–जंघई रेल मार्ग पर बृहस्पतिवार को छह ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चार घंटे तक विलंब से चलीं। इसको लेकर रेलयात्रियों को परेशानी हुई। सबसे अधिक नई दिल्ली–बनारस 15128 केवी एक्सप्रेस चार घंटे लेट रही। वह सुबह 6 बजे भदोही पहुंची। इसके अलावा पांच अन्य ट्रेनें दो घंटे या इससे अधिक विलंबित रहीं। सबसे अधिक केवी एक्सप्रेस ने ही रुलाया। पहले यह ट्रेन सुबह देरी से भदोही पहुंची। इसके बाद वापसी में भी यह ट्रेन लगभग पौने तीन घंटे विलंब से भदोही आई। स्टेशन अधीक्षक बीबी मिश्रा ने बताया कि केवी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से एक घंटे विलंब से चलाया गया था। बाद में इसी ट्रेन को वापसी में बनारस से दो घंटे देरी से चलाए जाने से दिक्कत हुई। यही स्थिति जोधपुर–वाराणसी सिटी 14866 मरुधर एक्सप्रेस का भी रहा तो तीन घंटे विलंब से जोधपुर से छोड़े जाने से ढाई घंटे विलंब से भदोही पहुंची। तीन ट्रेनें एक घंटे या इससे विलंबित रहीं। इसमें गोरखपुर–एलटीटी 15018 काशी एक्सप्रेस 1.20 घंटे, देहरादून–बनारस 15120 जनता एक्सप्रेस और अमृतसर–हावड़ा 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस दोनों 1.40 घंटे विलंब से भदोही स्टेशन पर पहुंचीं।

रोडवेज चालक के लिए 35 ने किया आवेदन

भदोही, (संवाददाता)। नगर के दुर्गागंज तिराहे के पास स्थित रोडवेज बस स्टेशन में बृहस्पतिवार को संविदा चालक नियुक्ति को लेकर शिविर आयोजित किया गया। इसमें कुल 35 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया। रोडवेज विभाग के केके सोनकर और इकबाल अंसारी ने सभी के प्रमाणपत्र को जमा किया। कर्मचारियों ने बताया कि जो अभ्यर्थी यहां आवेदन नहीं कर पाए हैं वह वाराणसी स्थित कार्यालय आकर जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार में चयन होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में व्यापार और मैनुफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा'

'लखनऊ।' पीएचडी चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पीएचडी हाउस में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो (यूपीआईटेक्स 2026) के चौथे संस्करण का कर्टेन रेजर सफलतापूर्वक आयोजित किया। इसके अलावा पीएचडीसीसीआई ने फर्स्टव्यू मीडिया ग्रुप के सहयोग से यूपी एनर्जी एक्सपो (यूपीईएक्स) 2026 के दूसरे संस्करण की भी घोषणा की। यह एक्सपो 07दृ09 मई 2026 को आयोजित होगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर श्री राजेश निगम को–चेयर यूपी स्टेट चौप्टर पीएचडीसीसीआई, श्री अजय कुमार सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर यूपीनेडा, श्री अतुल श्रीवास्तव सीनियर रीजनल डायरेक्टर पीएचडीसीसीआई, श्री सुधीर बिश्नोई डायरेक्टर एंड हेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। पीएचडीसीसीआई के को–चेयर, यूपी स्टेट चौप्टर, श्री राजेश निगम ने बताया कि यूपीआईटेक्स 2026 का आयोजन 23दृ27 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सपो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विविधता को एक ही मंच पर प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। इस बार इसे और वृहद स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। हमारा मानना है कि यूपीआईटेक्स राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में यूपीनेडा के सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री अजय कुमार ने कहा कि एक ओर यूपीआईटेक्स के माध्यम से व्यपार और मैन्यूफैक्चरिंग की संभावनाएं विकसित हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी एनर्जी एक्सपो के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में नए निवेश और तकनीकों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित होगा, जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य है कि यूपी न केवल भारत का सबसे बड़ा बाजार बने बल्कि निवेशकों और निर्यातकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य भी बने। इसी क्रम में, 07दृ09 मई 2026 को आयोजित होने वाला यूपी एनर्जी एक्सपो (यूपीईएक्स) 2026 का दूसरा संस्करण ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगा। यह मंच सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरती तकनीकों, ऊर्जा प्रबंधन, नीति सुधार और निवेश से जुड़े नए अवसरों पर चर्चा का बड़ा केंद्र बनेगा। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पीएचडीसीसीआई के सीनियर रीजनल डायरेक्टर श्री अतुल श्रीवास्तव ने कहा, "उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते औद्योगिक प्रदेशों में शामिल है। ये दोनों एक्सपो न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ाएंगे, बल्कि राज्य के उद्यमियों, निर्माताओं और निवेशकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने में मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिभागी इन आयोजनों में शामिल हों और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दें।"

चुनाव आयोग भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है : राजेश तिवारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित एक बैठक में कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है और मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम विपक्षी मतदाताओं के नाम काटने का हथियार बन गया है। तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकतंत्र और संविधान बचाने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि पार्टी का हर कार्यकर्ता गांव–गांव और बूथ–बूथ जाकर मतदाताओं को जागरूक करे। साथ ही, एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) फॉर्म भरने में जनता की मदद करे और वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखे। राजेश तिवारी ने इस स्थिति को लोकतंत्र और देश को शुगुलामी से बचाने के लिए शीत युद्धश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह और तानाशाहश भारत के संविधान को बदलकर संघ का विधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र बचाने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। इस दौरान, राजेश तिवारी ने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की। बैठक को पूर्व विधायक विजय प्रकाश, सुधाकर तिवारी, मणीन्द्र मिश्रा, श्रीमती मंजू संत, राजेश राकेश, राजेश दुबे और सत्यवीर सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव पंकज सोनकर, देवराज पांडेय, विनय तिवारी, लाल प्रकाश पाल, संतोष गिरी, रामचन्द्र पांडेय, रेखा सिंह, इरशाद खघन, शिव मिश्रा, रामसिंह बांकुरे, महात्मा शुक्ला, विपिन शर्मा, अरविंद यादव, प्रवेश निषाद, सुबास सिंह सहित कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

11 केंद्रों पर होगी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा

भदोही, (संवाददाता)। जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की छठवीं कक्षा में होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरु हो गई है। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4261 छात्र–छात्राएं शामिल होंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने वाली परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष भी नामित हो गए हैं। जल्द ही स्टेटिक और जोनल मजिस्ट्रेट संग पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर में कक्षा छह में 80 सीटें निर्धारित हैं। जिसमें प्रवेश के लिए हर साल परीक्षा कराई जाती है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में प्रतिभाग को 4261 छात्र–छात्राओं ने आवेदन किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. इकरामुद्दीन सिद्दिकी ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कराने की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की ओर से नामित अफसरों की निगरानी में परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए 4261 छात्र–छात्राओं ने आवेदन किया है। छह ब्लॉकों में कुल 11 केंद्रो पर परीक्षा होगी। ज्ञानपुर ब्लॉक में विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर, जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज ज्ञानपुर को केंद्र बनाया गया है। औराई ब्लॉक में राम संजीवन लाल इंटर कॉलेज खमरिया, काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज औराई और इंटर कॉलेज बाबूसराय, भदोही ब्लॉक में वुडवर्ड पब्लिक स्कूल व प्रेमबहादुर सिंह पब्लिक स्कूल, डीघ ब्लॉक में पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर कॉलेज सागर रायपुर, ओम पब्लिक स्कूल छतमी, सुरियावां ब्लॉक में बीपीएमजी पब्लिक स्कूल और अभोली ब्लॉक में श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज कनकपुर शामिल है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को केंद्राध्यक्ष बनाया गया है।

टोलप्लाजा के पास गरजा बुलडोजर, हटा अतिक्रमण

भदोही, (संवाददाता)। औराई के लालानगर स्थित टोल प्लाजा पर हाईवे के आसपास लगी दुकानों को बृहस्पतिवार को हटाया गया। एनएचआई और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इससे दुकानदारों में खलबली रही। लालानगर टोल प्लाजा के पास सड़क के किनारे अवैध ढंग से कई दुकानें लगाई गई थीं। इससे वहां रुकने वाले ग्राहकों के वाहन हाईवे पर ही खड़े रहते थे। इससे अक्सर जाम लगता और घटनाएं भी होती। पूर्व में दुकानदारों को चेतावनी देकर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन वह नहीं हटाए। बृहस्पतिवार को पुलिस और एनएचआई टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान कई दुकानों को जेसीबी लगाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान विनोद कुमार, सुरेश कुमार, रामजी पाल, शिव शंकर की चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक के साथ अन्य दुकानें हटाई गईं। टोल प्रबंधक राकेश रंजन ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।

देवरानी को अस्पताल में देखने आई महिला ने चुराया नवजात

गोरखपुर, (संवाददाता)। यूपी के कुशीनगर स्थित मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग से चोरी गए नवजात सकुशल पडरौना कोतवाली के मनिकौरा गांव के पश्चिम टोला से पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस की सक्रियता के चलते 30 घंटे बाद सफलता मिली। नवजात को चोरी करने वाली महिला घर छोड़कर भाग गई है। पुलिस के अनुसार वह अपनी चचेरी देवरानी के बच्चे को देखने मेडिकल कॉलेज में आई थी और रात में रेकी करने के बाद नवजात को चुरा ले गई। नवजात के बरामद होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। नवजात को वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। पडरौना कोतवाली के मनिकौरा गांव निवासी माया देवी के चचेरी देवरानी पूनम देवी को तीन दिन पूर्व प्रसव मेडिकल कॉलेज में हुआ था। देवरानी की बेटी एमसीएच विंग में भर्ती थी। इसे देखने के लिए मंगलवार को माया गई थी। पूरी रात रेकी करने के बाद बुधवार को एमसीएच वार्ड में भर्ती रीना के नवजात बेटे को उसकी मां बनकर दूध पिलाने के बहाने चोरी कर लेती गई। नवजात चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। जांच में जुटी पुलिस को मेडिकल कॉलेज से मिले सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नहीं कुछ दिखाई दिया, इसके बाद पुलिस दिन और समय के हिसाब से रविंद्र नगर से पडरौना तक वह महिला गोद में लेकर जा रही है। इसके बाद एसपी ने चारों

तरफ गायब नवजात के बारे में जानकारी के लिए पंपलेट चस्पा कराने के अलावा सोशल मीडिया पर भी वायरल कराए थे, मनिकौरा के प्रधान प्रतिनिधि हरेंद्र साहनी ने बताया कि शाम को करीब 7 बजे गांव की माया देवी आई और बताई कि मेडिकल कॉलेज से जो नवजात गायब हुआ है। उसे मैं लाई हूं, इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि उसे घर जाकर देखते हुए कपड़े में लिपटा नवजात पड़ा है। इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि ा ने एसपी को जानकारी दिया। प्रधानपति ने कपड़ा खरीदकर नवजात के लिए मंगाया। इसके बाद महिला अपने बच्चियों को घर पर छोड़कर भाग गई है। इसकी भनक आस–पास के लोगों को भी नहीं लगी।

बीआरडी के नशामुक्ति केंद्र से दवा की 9,500 गोलियां चोरी, दस्तावेज जलाए

गोरखपुर, (संवाददाता)। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में संचालित नशामुक्ति केंद्र (ओएसटी) में मंगलवार शाम दो मिलीग्राम की दवा की करीब 9,500 गोलियां चोरी कर ली गईं। विभाग में रखे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जले मिले। जानकारी होने पर विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को इसकी सूचना दी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर पहले ओएसटी कक्ष में घुसे। यहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन रजिस्टर और टेबल पर रखे कागजात जला दिए। इसके बाद मानसिक रोग विभाग की ओपीडी के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। विभाग की आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखीं दो मिलीग्राम की 9,500 गोलियां चोरी कर लीं। ये सभी दवाएं नाक के माध्यम से उन मरीजों को दी जाती थीं, जो नशा छोड़ने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दवाओं की चोरी और दस्तावेज जलाने पर ओएसटी की पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विभागाध्यक्ष ने घटना की लिखित सूचना कॉलेज प्राचार्य को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से मानसिक रोग विभाग में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन अब तक सुरक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से खराब पड़े हैं।

प्राइवेट सेंटर चलाने वाली महिलाकर्मी शक के दायरे में

गोरखपुर, (संवाददाता)। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में संचालित नशामुक्ति केंद्र (ओएसटी) में मंगलवार रात हुई चोरी ने विभागीय कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र से जुड़े एक स्टाफ की ओर से संचालित प्राइवेट सेंटर भी जांच के दायरे में है। चोरी हुए लैपटॉप में नशामुक्ति केंद्र की दवाओं के स्टॉक का रिकॉर्ड, प्रतिदिन आने वाले मरीजों का डेटा और अन्य महत्वपूर्ण विवरण सुरक्षित थे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रजिस्टर को भी जला दिया गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि चोरी का मुख्य उद्देश्य दवाओं को गायब करना था, क्योंकि इनकी मार्केट में भारी मांग है। नशामुक्ति केंद्र में उपयोग की जाने वाली दवाएं केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं, जबकि प्राइवेट सेंटरों में इन दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है ।

तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो में प्रदेश के खास उत्पादों की होगी प्रदर्शनी

गोरखपुर, (संवाददाता)। गीडा स्थापना दिवस समारोह इस बार प्रदेश के उद्योग और पारंपरिक उत्पादों को नया आयाम देने जा रहा है। 29 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं और निवेश से जुड़ी सौगात देंगे। इसी के साथ तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भव्य आगाज होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीओपी और विशेष उत्पादों को एकीकृत मंच मिलेगा। गीडा में निर्मित उत्पादों के साथ ही कानपुर के टेक्सटाइल एवं लेदर गुड्स, लखनऊ की चिकनकारी, वाराणसी का सिल्क, गाजीपुर के हैंडीक्राफ्ट, बाराबंकी के मेंथाल उत्पाद सहित कई जिलों की विशिष्ट पहचान वाले सामान प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। गोरखपुर की ओडीओपी सूची में शामिल टेराकोटा उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस बार एक खास पहल के रूप में गोरखपुर की महिला उद्यमी प्रियंका सिंह भी केले के रेशे से बने 'बनाना फाइबर गुड्स' प्रदर्शित करेंगी, जो नवाचार और पारंपरिक कौशल का अनूठा संयोजन पेश करेंगे।

कल चलेगी छपरा-चेन्नई सेंट्रल वाया गोरखपुर स्पेशल

गोरखपुर, (संवाददाता)। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने 05081 छपरा–चेन्नई सेंट्रल वाया गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन छपरा से 29 नवंबर को एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। 05081 छपरा–चेन्नई सेंट्रल पूजा स्पेशल 29 नवंबर को छपरा से रात 10:10 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर से देर रात 02:26 बजे छूटकर बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं., भोपाल, तीसरे दिन नागपुर, विजयवाड़ा, गुडूर होकर चेन्नई सेंट्रल सुबह 04:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन एलएसआरडी के दो, शयनयान श्रेणी के 14 एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के एक कोच सहित कुल 17 कोच लगाए जाएंगे।

नहीं मिला पूर्व ईडी के बेटों की उपस्थिति वाला रजिस्टर, होगी जांच- लगे हैं ये गंभीर आरोप

गोरखपुर, (संवाददाता)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर की पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर के दोनों बेटों के हस्ताक्षर वाला रजिस्टर गायब होने से हड़कंप मचा गया है। अब एम्स प्रशासन ने इस मामले में जांच कराने का निर्णय लिया है। उधर, एम्स की तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ सुरेखा किशोर पर लगे आरोपों पर ऋषिकेश एम्स ने भी पत्रावलियों की जांच शुरू कर दी है। एम्स गोरखपुर ने बुधवार को ऋषिकेश प्रबंधन को लिखित सूचना देकर बताया है कि ऐसा कोई रजिस्टर प्रशासनिक दस्तावेजों में नहीं है। अब इसकी जांच कराई जाएगी। एम्स ऋषिकेश से जून 2020 में गोरखपुर एम्स का कार्यकारी निदेशक बनने वाली डॉ. सुरेखा किशोर पर अपने दोनों बेटों डॉ. शिखर किशोर वर्मा और डॉ. शिवल किशोर वर्मा को एम्स, गोरखपुर में जेआर पद पर नियुक्ति देने का आरोप था। इस मामले को पिछले साल एम्स, ऋषिकेष ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले में डॉ सुरेखा किशोर के अलावा तीन से चार लोगों को भी दोषी माना गया था। पूर्व जांच के दौरान पूर्व ईडी पर पर आरोप लगा था कि नियुक्ति ही नियमों को दरकिनार कर नहीं की गई थी, बल्कि दोनों बेटों को बिना नौकरी किए ही वेतन भी ले लिया था। एक शिकायत पर विजिलेंस ने जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को दी थी, जिसके आधार पर जनवरी 2024 में उन्हें हटाकर एम्स पटना के प्रभारी कार्यकारी निदेशक डॉ. जीके पाल को गोरखपुर के कार्यकारी निदेशक का चार्ज दिया गया था। 2020 से पूर्व एम्स गोरखपुर का कार्यभार संभालने से पहले वह एम्स ऋषिकेश की डीन थी। एम्स ऋषिकेस में जांच शुरू हुई तो पूर्व कार्यकारी निदेशक ने फोटो कॉपी को संदिग्ध बताते हुए मूल हस्ताक्षर वाला रजिस्टर मंगाने की बात जांच टीम से कही। इसके बाद एम्स ऋषिकेश प्रशासन ने गोरखपुर एम्स प्रशासन से रजिस्टर मांगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।